लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3608

16 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

इस्पात की मांग और कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन

3608. श्री ए. राजाः

श्री इंद्रा हांग सुब्बाः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में इस्पात की मांग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात की मांग में वर्ष-दर-वर्ष बढोत्तरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इस्पात की मांग मौजूदा 111 मिलियन टन का चार गुणा बढ़कर 489 मिलियन टन होने की संभावना है और यदि हां, तो बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विश्व संवहनीयता विकास शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारतीय इस्पात क्षेत्र से कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़कर 837 मिलियन टन (एमटी) होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कम कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके इस्पात क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अर्थात् अप्रैल, 2019-जनवरी, 2020) (अनंतिम) के दौरान प्रतिशत परिवर्तन सहित उपर्युक्त अवधि के दौरान खपत में वृद्धि को दर्शाते हुए तैयार (फिनिश्ड) इस्पात की खपत की मात्रा निम्नानुसार है:

अवधि	**तैयार (फिनिश्ड) इस्पात की कुल खपत (अलॉय/स्टेनलेस + नॉन-अलॉय)**	
	मात्रा (मिलियन टन)	**% परिवर्तन**
2016-17	84.04	3.1
2017-18	90.71	7.9
2018-19	98.71	8.8
अप्रैल 2019 - जनवरी 2020*	83.90	3.8
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम		

(ग): यह आशा है कि जीडीपी विकास की मौजूदा दर के आधार पर इस्पात की माँग राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2030-31 तक 230 मिलियन टन तक पहुँचने के लिए लगभग तीन गुणा तक बढ़ जाएगी। सरकार ने इस्पात की माँग को बढ़ाने के लिए रेलवे, सड़कों, '2022 तक सभी के लिए आवास', हर घर के लिए नल से पानी जैसी बेहतर अवसंरचना के लिए सरकारी प्रयास के साथ-साथ स्वदेशी विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद खरीद (डीएमआई एंड एसपी) नीति, इस्पात स्क्रैप नीति, इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को तैयार किया है। बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए नियंत्रणमुक्त इस्पात क्षेत्र में बाजार तंत्र कार्य करेगा।

(घ): वर्ष 2050 तक 837 एमटीपीए कार्बन डाई-ऑक्साईड के उत्सर्जन के अनुमान का आधार सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ङ): इस्पात उद्योग एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। विश्वस्तरीय नवीनतम प्रौद्योगिकी की शुरुआत संबंधी निर्णय वास्तव में तकनीकी-आर्थिक आधार पर संबंधित लौह एवं इस्पात कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं। इस्पात मंत्रालय, इस्पात निर्माण के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

****